Statement

Poverty Lines for 1996-97 as per the new official methodology

(Rs. monthly per capita)

State	Rural	Urban
1. Andhra Pradesh	216.65	344.40
2. Arunchal Pradesh	280.85	271.71
3. Assam	280.85	271.71
4. Bihar	263.13	305.50
5. Goa	266.97	419.98
6. Gujarat	254.00	373.16
7. Haryana	289.31	337.42
8. Himachal Pradesh	289.31	300.91
9. Jammu & Kashmir	258.74	302.58
10. Karnataka	255.12	385.40
11. Kerala	327.48	372.96
12. Madhya Pradesh	245.70	364.45
13. Maharashtra	266.97	419.98
14. Manipur	280.85	271.71
15. Meghgalaya	280.85	271.71
16. Mizoram	280.85	271.71
17. Nagaland	280.85	271.71
18. Orissa	249.69	287.37
19. Punjab	289.31	300.91
20. Rajasthan	273.65	356.72
21. Sikkim	280.85	271.71
22. Tamil Nadu	269.07	381.04
23. Tripura	280.85	271.71
24. Uttar Pradesh	272.53	320.84
25. West Bengal	274.35	313.12
26. Andaman & Nicobar	269.07	381.04
27. Chandigarh	300.91	300.91
28. Dadra & Nagar Haveli	266.97	419.98
29. Daman & Diu	266.97	419.98
30. Delhi	289.31	404.96
31. Lakshadweep	327.48	372.96
32. Pondicherry	269.07	381.04
ALL INDIA	266.27	353.44

1. Poverty line of Assam is used for Sikkim, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nagaland and Tripura.
2. Poverty line of Tamil Nadu is used for Pondicheery and A & N Island.
3. Poverty line of Kerala is used for Lakshadweep.
4. Poverty line of Maharashtra is used for Goa, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.
5. Urban Poverty line of Punjab is used for both rural and urban areas of Chandigarh.

गरीबी रेखा के संबंध में आकलन

2606. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 36 प्रतिशत के लगभग थी;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कितनी आय वाले व्यक्ति को गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाला माना गया है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने लोगों के होने का आकलन है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा किए गए पंचवार्षिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का अनुमान लगाता है। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण 1993-94 में किया गया था। अत:, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में अर्थात् 1996-97 को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत के अनुमान उपलब्ध नहीं है। एन एस एस ओ के 50वें दौर के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के प्रतिशत के नवीनतम अनुमान के अनुसार, 1993-94 में 35.97 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी।

(ग) कुल जनसंख्या में गरीबी के प्रतिशत और संख्या के अनुमान के मानदंड के रूप में प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय का उपयोग किया जाता है, न कि आय का। योजना आयोग मार्च, 1997 से, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के अनुमान के लिए गरीबी के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल की सिफारिशों का पालन करते हुए राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाओं का उपयोग करता रहा है। राज्यवार गरीबी रखाओं के नवीनतम अनुमान वर्ष 1996-97 के लिए उपलब्ध है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संबंध में ये सलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(घ) चूंकि गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन से प्राप्त उपभोक्ता व्यय पर पंचवार्षिक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों से लगाए जाते हैं। अत: नौवी

संगठन से प्राप्त उपभोक्ता व्यय पर पंचवार्षिक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों से लगाए जाते हैं। अत: नौवी पंचवर्षीय योजना अर्थात् 2001-2002 के अंत तक के गरीबी के अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि, योजना आयोग से नौवीं पंचवर्षीय योजना प्रक्रियाओं में नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात् 2001-2002 तक समग्र रूप से देश के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के प्रतिशत का अनुमान 17.98 प्रतिशत लगाया है। वर्ष की अनुमानित जनसंख्या की दृष्टि से नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गरीबों की संख्या 184 मिलियन बैठती है।

विवरण

नई सरकारी कार्यप्रणाली के अनुसार वर्ष 1996-97 के लिए गरीबी की रेखा

(रुपये प्रति व्यक्ति मासिक)

	राज्य	ग्रमीण	शहरी
1.	आन्ध्र प्रदेश	216.65	344.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	280.85	271.71
3.	असम	280.85	271.71
4.	बिहार	263.13	305.50
5.	गोवा	266.97	419.98
6.	गुजरात	254.00	373.16
7.	हरियाणा	289.31	337.42
8.	हिमाचल प्रदेश	289.31	300.91
9.	जम्मू और कश्मीर	258.74	302.58
10.	कर्नाटक	255.12	385.40
11.	केरल	327.48	372.96
12.	मध्य प्रदेश	245.70	364.45
13.	महाराष्ट्र	266.97	419.98
14.	मणिपुर	280.85	271.71
15.	मेघालय	280.85	271.71
16.	मिजोरम	280.85	271.71
17.	नागालैंड	280.85	271.71
18.	उड़ीसा	249.69	287.37
19.	पंजाब	289.31	300.91
20.	राजस्थान	273.65	356.72
21.	सिक्किम	280.85	271.71
22.	तमिलनाडु	269.07	381.04
23.	त्रिपुरा	280.85	271.71
24.	उत्तर प्रदेश	272.53	320.84
25.	पश्चिम बंगाल	274.35	313.12
26.	अ.व.नि. द्विप समूह	269.07	381.04
27.	चण्डीगढ़	300.91	300.91
28.	दादरा व नगर हवेली	266.97	419.98
29.	दमन और दीव	266.97	419.98
30.	दिल्ली	289.31	404.96
31.	लक्ष्यद्वीप	327.48	372.96
32.	पांडिचेरी	269.07	381.04
	अखिल भारतीय	266.27	353.44

1. असम की गरीबी रेखा का प्रयोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणीपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए किया जाता है।
2. तमिलनाडु की गरीबी रेखा का प्रयोग पांडिचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए किया जाता है।
3. केरल की गरीबी रेखा का प्रयोग लद्दखेप के लिए किया जाता है।
4. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा का प्रयोग गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव के लिए किया जाता है।
5. पंजाब की शहरी गरीबी रेखा का प्रयोग चण्डीगढ़ के ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए किया जाता है।

Schemes for Upliftment of Poor

2607. SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the reduction of poverty and the upliftment of the poor are a part of the objectives of the Ninth Five Year Plan;

(b) if so, the details thereof and number and names of specific schemes included in the draft plan for achieving these objectives;

(c) the total funds earmarked for the schemes; and

(d) whether these schemes include any provision for creating infrastructural facilities in the rural sector and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) Yes, Sir.

(b) The Government has adopted a three pronged strategy for reducing poverty (i)